श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि समाज का कौन-सा वर्ग सबसे ज्यादा सेलुलर फोन इस्तेमाल करता है?

श्री प्रमोद महाजन: संभवत: एम०पीज़०। क्योंकि इसीलिए यहां पर फोन को यूस करना बैन किया गया है।

Non-remittance of provident fund contribution

*428. SHRI J. CHITHARANJAN†:

SHRI MOTILAL VORA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number as well as the names of the employers and companies that have defaulted in remitting the provident fund contribution to EPF during the last two years;

(b) the action taken to realise the arrears;

(c) what action has been taken against those defaulting employers and companies;

(d) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Kai Sal Se P.F. Ki Rakam Jama Nahin Karai" appearing in the 'Rashtriya Sahara' dated the 30th June, 2002;

(e) if so, the action taken in the matter?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA) (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Some of the establishments have defaulted in the payment of statutory Provident Fund dues throughout the country. The number of establishments who have defaulted for an amount of Rs 10 lakhs or more is 845 in 2000-2001 and 863 in 2001-2002, and a large number of establishments have defaulted for an amount below Rs. 10 lakhs. It is not possible to furnish a list of all defaulting establishments as this list will be too large. As on 31-3-2002, the total default was Rs. 1336 crores, out of which 77.32% is currently unrealisable being the amount locked up in court stays, establishments registered with BIFR, etc. The default constitutes only 1.3% of total holding of Rs. 1,02,163.06 crore in

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri J. Chitharanjan.

Employees' Provident Fund, Pension Scheme and Employees' Deposit Linked Insurance Scheme put together.

Whenever any default is detected, actions under sections 7A, 8F, 8B to 8G, 14(1)(A), 14(B) & 7(Q) of Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952, under section 406/409 of Indian Penal Code, and under section 110 of Criminal Procedure Code, are taken against defaulters.

(d) and (e) The news-item captioned "Kai Sal Se PF Ki Rakam Jama Nahin Karai" appeared on 30th July, 2002 in "Rashtriya Sahara". An enquiry under section 7A of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 has been initiated against M/s. Precision Gauge and Tools, Noida, UP. The establishment had approached the Hon'ble Allahabad High Court to stay the proceedings under section 7A. The Hon'ble Court has dismissed the petition. The EPFO is going ahead with the enquiry. Directions have also been issued to file FIR against the employers.

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, in the reply, the Minister has stated that the default is very much minimal. He has even gone to the extent of saying that the default constitutes only 1.8 per cent of the total. Sir, I know even there are so many cases where factories which employ 500 or 1000 workers, the employer remit the PF contribution for only 200, and there it lies. They do not even give the addresses of the workers and they cannot proceed against them and that continues for years together. This cannot be done without the connivance of the officers.

Then, number two; you see the employers collect employees contribution from the workers. There are umpteen cases or thousand cases, where the money collected from the wages of the workers as their contribution towards the provident fund has not been remitted. It is a criminal offence and no action has been taken against them.

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि कुछ ऐसे उद्योग हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, लेकिन सब भविष्य निधि अंशदान नहीं देते हैं। ऐसे ही करीब-करीब, 80,000 केसेज हमारे कोर्ट में हैं, जिनके ऊपर कार्यवाही चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि सब नहीं देते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे उद्योग हैं जिसमें नहीं देते हैं। माननीय सदस्य की जानकारी में अगर कोई ऐसे खास उद्योग हैं, जहां पर ऐसा होता है तो वह उसके बारे में हमें जानकारी दें, हम उनके खिलाफ कार्यवाही करवाएंगे। अभी तो हमने यह अभियान शुरू

किया है, जिसमें देश भर में हमारे जितने भी इंस्पेक्टर हैं क्योंकि पहले जैसे एक इंस्पेक्टर एक एरिए के लिए मुकर्रर होता था तो उसमें कहीं-कहीं पर यह पाया गया कि उनके साथ कनाइवेन्स होती थी, अब उस एक एरिए में अन्य इंस्पेक्टर को लेकर एक अभियान चलाया है ताकि किसी के साथ किसी की अंडरस्टैंडिंग न हो और वे वहां जाकर जांच करें और जहां कवरेज नहीं हुआ है वहां उसको पूरा करवाएं।

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, the Minister says that action will be taken against the defaulters. He has said that the Department will take action on the basis of several clauses in the Employees' Provident Fund Scheme. But from the working of that Scheme and the actual experience, what we have seen, for years together in the case of some people or some companies, no action has been taken. Sir, at the same time, some companies which have remitted the money, of course, there was a little delay, against them, very huge penalties are being imposed. There is a discrimination in all these things. Will the Minister try to avoid such things?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात दिलाना चाहूंगा कि अभी तक 2.6 करोड़ लोग थे, जो इसमें कवर होते थे, हमारे बैटर एन्फोर्समेंट की वजह से...now the number has gone up to 3.25 crores. But I agree that there can be many such cases, and we are taking action against them. We are not leaving any stone unturned. And whatever defects are there in the laws, we are going to rationalise all the existing laws. We will see to it that they improve...(*Interruptions*)

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने प्रतिष्ठान हैं जिनके विरुद्ध 77.32 प्रतिशत धनराशि वसूल करना बाकी है? आपने कुल राशि जो बतलाई है वह 1336 करोड़ रुपए बतलाई है और 1336 करोड़ की धनराशि में से 77.32 प्रतिशत धनराशि वसूल करना बाकी है, यह आपने बतलाया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने प्रतिष्ठान हैं जिनके विरुद्ध धनराशि नहीं देने का आरोप है?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, यह पूरी सूचना अभी तो मेरे पास नहीं है। हां, 1336 करोड़ की जो कुल राशि है उसमें से 77.32 प्रतिशत कोर्ट के स्टे आर्डर के कारण रुकी पड़ी है, लेकिन इसमें कौन-सी कम्पनीज हैं, कौन-सी नहीं हैं, अगर माननीय सदस्य वह डिटेल चाहते हैं तो मैं उनको बाद में दे दूंगा।

श्री दीपांकर मुखर्जी: 'दीपक तले अंधेरा'. The Government is supposed to detect the defaulters. I had raised a Special Mention on 30th July which

still remains unanswered by the Ministry of Labour. In that Special Mention, I had pointed out an article by a Cabinet Minister in the *Indian Express* where he had charged that the public sector companies owed about Rs. 600 crores of EPF as default. He had also charged that because they were in the public sector, no action had been taken against the defaulting companies. I would like to know from the hon. Minister, unless this रक्षक अगर भक्षक नहीं है, तो आप बताएं कि रक्षा के लिए आपने अपने केबिनेट मिनिस्टर के स्टेटमेंट के हिसाब से कितने पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स के अगेंस्ट, जो पी॰एफ॰ डिफॉल्टर्स हैं, एक्शन लिए हैं और कितना पी॰एफ॰ ड्यू बाकी है पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कम्पनीज पर?

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, इस प्रश्न में यह तो नहीं था, अलग था, लेकिन यह बात सही है कि आज हमारे जितने पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके पास काफी ड्यूज हैं और जो लॉस-मेकिंग पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके पास तो खासतौर से हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यह कहना गलत है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, हम उन सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार की संस्था होने के नाते हम किसी के खिलाफ कार्रवाई न कर रहे हों।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, the Cabinet Minister, Shri Arun Shourie, writes this in his article. If he is wrong, he should take action against that Cabinet Minister who he is giving wrong information to the country. प्रैस में, इंडियन एक्सप्रैस में यह पब्लिश हुआ है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, काफी गंभीर बात है। पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में पैसा बाकी रहे, वह जमा नहीं हो तो यह काफी गंभीर विषय है और आप इसको गंभीरता से लें और इसका समाधान करें।

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि करीब 200 करोड़ रुपया अभी ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: मेरे को नहीं, आप वेरिफाई कीजिए मिस्टर अरुण शौरी से।

SHRI SAHIB SINGH VERMA: He should listen to me also.

श्री सभापति: अरुण शौरी जी की इनको जानकारी नहीं है। जब इन्होंने कहा कि हां, ड्यू है तो खत्म हुआ किस्सा।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, if wrong information is being given by a Cabinet Minister in an article, he should clarify it in the newspaper, not here. (*Interruptions*)

श्री साहिब सिंह वर्मा: आपका यह कहना कि हम उनसे वसूल नहीं करते हैं, सही नहीं है। पिछले दो वर्षों में जितने भी पी॰एस॰यू॰ हैं, उनसे हमने 200 करोड़ रुपया वसूल किया है। इसलिए आपका यह कहना कि हम रिकवरी नहीं करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, सही नहीं है। हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उनसे रिकवरी करते हैं और हमने पिछले दो वर्षों में 200 करोड़ रुपया रिकवर किया है।

श्री दीपांकर मुखर्जी: यह मैं नहीं कह रहा, आपके एक केबिनेट मिनिस्टर कह रहे है।

श्री साहिब सिंह वर्मा: मुझे नहीं पता कि अरुण शौरी जी ने क्या कहा था। यह प्रश्न उनका तो है नहीं, यह प्रश्न आपका है। ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: आपने शायद देखा नहीं, मेरा स्पेशल मेंशन 6 महीने से पड़ा हुआ है। ...(**व्यवधान**)...

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: सर, आप इस क्वेश्चन को पोस्टपोन कर दीजिए, मंत्री के पास अभी पूरी इन्फॉरमेशन नहीं है, ये कल लेकर आएं। ...(**व्यवधान**)...

श्री खान गुफरान जाहिदी: इनके पास आज इन्फॉरमेशन नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: पोस्टपोन नहीं। दीपांकर जी, मैंने आपकी बात को गंभीरता से लिया है और गंभीरता से ही मंत्री जी को कहा है। श्री विरुम्भी।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, so far as the EPF arrears are concerned, the main problem is that some companies are ...(*Interruptions*)

श्री सभापति: आप प्रश्न पूछिए।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, I am putting it from a different angle. Only after a company is closed, its employees come to know that it has not paid its dues. Therefore, there should be transparency in the system. I feel it is a systemic failure. How will the employees know that the employer has not paid his EPF contribution? So, there should be some mechanism. I think this information should be displayed on the notice board of the company so that the employees can know it. The mechanism that is available at present is a total failure. Will the Government see to it that a new mechanism is put in place so that the employees can know that their employers have failed to pay their EPF contribution?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, माननीय सदस्य ने अभी एक प्रश्न पूछा था, जिसका जवाब अधूरा था, मैं उसका जवाब पूरा कर दूं कि कुल मिलाकर 31.3.2002 तक 478.7 करोड़

रुपया CPSUs के खिलाफ बकाया था। उसमें से Rs. 125.99 crores was recovered in one year. Out of the total default of Rs. 478.74 crores, an amount of Rs. 265.66 crores is locked up due to cases pending before the BIFR, and Rs. 18.34 crores are locked up because of stay orders. Thus, a total amount of Rs. 284 crores, which is 59.32 per cent of the total default, is unrealisable. All possible actions for recovery, as provided in the law, are being taken to recover the outstanding amount. No relaxation or leniency is being shown towards those CPSUs.

इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि उनके खिलाफ हम कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और हम उनको छोड़ रहे हैं, दीपक तले अंधेरा है, यह कहना सरासर गलत है और यह कहना ठीक नहीं है। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिए, गलत है या सही, यह मैं नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज़ यदि डिफॉल्टर रहती हैं तो गवर्नमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी से बच नहीं सकती है।

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, मैंने अभी जानकारी दी है। यह बात सही है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है, what to talk of CPSUs. I mean, the CPSUs are not being treated differently. But, as I told you, there are stay orders ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Question No. 429. Shri Rajkumar Dhoot.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, he has replied to the point raised by my colleague. But he has not replied to my question. (*interruptions*) Sir, my question remains unanswered.

श्री सभापति: हो गया, उन्होंने कह दिया है। Question No. 429. Shri Rajkumar Dhoot.

Apprehensions on cross border terrorism by Pakistan

*429. SHRI RAJKUMAR DHOOT: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are apprehensive of more cross border terrorism with the formation of new elected Government in Pakistan;

(b) if so, whether Government have conveyed their apprehensions to the major powers and friendly countries besides UNO at appropriate diplomatic levels;